Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

नवंबर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 3
- जोधपुर में होगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो-2023 का आयोजन 3
- मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का उद्घाटन 4
- 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत नवीन सेवाएँ सम्मिलित करने के प्रस्ताव को मिली मंज़ूरी 4
- एआरटी एवं सरोगेसी एक्ट के संबंध में राज्यस्तरीय बोर्ड की पहली बैठक 5
- अलवर में नवजीवन परिवारों की महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण बैच का हुआ शुभारंभ 5
- जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 45 योजनाओं के लिये 628 करोड़ रुपए की स्वीकृति 6
- सात ज़िलों की छात्राओं ने महात्मा गांधी विद्यालय में सैटेलाइट और ड्रोन किया लॉन्च 6
- डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का जयपुर के जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में आयोजन 7
- प्रदेश के 60 हज़ार से अधिक सरकारी स्कूलों में शुरू होगा 'चेस इन स्कूल' कार्यक्रम 7
- 'जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल' 8
- जोधपुर डिजिफेस्ट-जॉब फेयर 2022 8
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 9
- जयपुर में आयोजित होगा दो-दिवसीय विश्व सूफी संगीत समारोह 'जहाँ-ए-खुसरो' 10
- नेशनल टैक्सेशन अवार्ड-2022 में राजस्थान को प्राप्त हुए दो गोल्ड पुरस्कार 11
- कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा देने हेतु गाइडलाइन्स-2022 11
- राजस्थान डिजिफेस्ट एंड जॉब फेयर का समापन 12
- चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ 13
- हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) एवं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मध्य एमओयू 14
- 41वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में राजस्थान मंडप का शुभारंभ 14
- अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ 15
- 66वीं राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ 15
- डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास 16
- अष्टम् राष्ट्रीय कोसीडीसी अवार्ड्स-2022 16
- विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक 17
- 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने जीता गोल्ड मेडल 18
- जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिये 993.51 करोड़ रुपए स्वीकृत 18
- भीलवाड़ा के शाहपुरा में केसरी सिंह बारहठ पेनोरमा का होगा निर्माण 19
- 'कृषि में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रोत्साहन योजना' 19
- बांसवाड़ा-नाथद्वारा, राजसमंद, बाड़मेर और उदयपुर बेल्ट में खनिज खोज का व्यापक एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम 19
- मुख्यमंत्री ने किया 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास 20
- राजस्थान आवासन मंडल स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चयनित 21
- राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए कई अहम निर्णय 21
- राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये ऑनलाइन पेंशन पोर्टल 22
- डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलेगी 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि 23
- जेम बॉर्स की स्थापना हेतु बैठक का आयोजन 23
- 'डॉ. अंबेडकर उत्सव धाम योजना' के अंतर्गत राजस्थान के 568 गाँवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण 24
- हरि सिंह उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधानकर्त्ता के रूप में सम्मानित 24
- आइईडी से निपटने में देश में तीसरे स्थान पर राजस्थान 25
- मुख्यमंत्री ने सेई एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिये 2,554 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी 25
- शिल्प गुरू और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए राजस्थान के शिल्पकार 25
- सहकारिता मंत्री ने किया मंडार ग्राम सेवा सहकारी समिति में 500 मीट्रिक टन वेयर हाउस का उद्घाटन 26
- सेफ्टी अगेंस्ट वॉइलेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन (सेव) का शुभारंभ 26
- 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' एवं 'नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना' का शुभारंभ 27

नोट :

राजस्थान

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022

चर्चा में क्यों ?

31 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 28 की विद्यमान उपधारा (7-क) हटाई गई है।

प्रमुख बिंदु

- अधिसूचना में हटाई गई धारा से कोई भी व्यक्ति अब संचालक मंडल में लगातार दो से अधिक अवधि के लिये निर्वाचित हो सकेगा। इससे सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- विदित है कि 20 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित किया था।
- विधेयक में सहकारी समितियों के दक्ष कार्यकरण के लिये लंबी सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप धारा (7-क) को हटाया गया था।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 28 की विद्यमान उप-धारा (7-क) यह उपबंध करती थी कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात् उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिये निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है।

जोधपुर में होगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो-2023 का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2022 को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद) की उद्योग भवन में आयोजित पाँचवी बैठक की अध्यक्षता करते हुए काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य से निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिये आगामी 11 से 13 मार्च, 2023 को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो-2023 का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राजीव अरोड़ा ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर ज्वैलरी, सेरेमिक व अन्य उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हैंडीक्रॉफ्ट एक्सपो का आयोजन मुख्यमंत्री बजट घोषणा का अहम हिस्सा है तथा इस एक्सपो को और व्यापक बनाने एवं कई अन्य उत्पादों को जोड़ने के लिये इसे राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का नाम दिया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में निर्यात का प्रतिशत बढ़ाने व निर्यात सहित अन्य गतिविधियाँ संचालित करने के लिये ही काउंसिल का गठन किया गया है।

नोट :

- आयुक्त महेंद्र पारख ने बताया कि निर्यात के मामले में राजस्थान देश में 12वें स्थान पर है और राज्य में निर्यात की खासी संभावनाएँ हैं। पिछले वर्षों में राज्य से होने वाले निर्यात के प्रतिशत में भी खासी बढ़ोतरी हुई है।
- उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपो होने से न केवल स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाज़ार मिलेगा, बल्कि उनकी पहचान भी बनेगी।
- काउंसिल की बैठक में उत्पादों की टेस्टिंग लैब बनाने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण, काउंसिल की मेंबरशिप की शुरुआत, मिशन निर्यातक बनो सहित विभिन्न विषयों पर भी व्यापक स्तर पर चर्चा भी हुई।

मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अजमेर स्थित पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला-2022 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि पुष्कर धाम सभी वर्गों की आस्था का केंद्र है तथा यहाँ सभी जाति और धर्मों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिये पुष्कर मेले में बृहद् स्तर पर उत्कृष्ट एवं भव्य व्यवस्थाएँ की गई हैं।
- इस अवसर पर उन्होंने अजमेर और पुष्कर में 110 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया है। इसमें स्मार्ट सिटी, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के तहत विभिन्न विकास कार्य और परियोजनाएँ शामिल थीं।
- उन्होंने बताया कि पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिये डीपीआर तैयार कर ली गई है और करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से पुष्कर का विकास कराया जाएगा एवं पुष्कर में घाटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य विकास कार्य जल्द पूरे किये जाएंगे।

'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत नवीन सेवाएँ सम्मिलित करने के प्रस्ताव को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने तथा मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये 'गुड गवर्नेंस'की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की नवीन सेवाओं को 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011' के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल, गृह विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आबकारी विभाग, ऊर्जा विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की विभिन्न नवीन सेवाओं को जोड़ने की मंज़ूरी दी गई है।
- इसके अलावा श्रम विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, नगरीय विकास विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, गृह विभाग में सेवाओं के लिये अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी/द्वितीय अपील अधिकारी में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री की इस मंज़ूरी से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक-से-अधिक लोगों को सुगमता से शीघ्र मिलना सुनिश्चित होगा और इससे विभागों की सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेशवासियों को सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं का पूर्ण लाभ प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 लाकर विभिन्न विभागों की सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया था।

नोट :

एआरटी एवं सरोगेसी एक्ट के संबंध में राज्यस्तरीय बोर्ड की पहली बैठक

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 एवं सरोगेसी (रेग्युलेशन) एक्ट, 2021 के संबंध में गठित राज्यस्तरीय बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में राज्य में एआरटी एवं सरोगेसी एक्ट के लागू होने से पूर्व जो एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक एवं सरोगेसी क्लीनिक कार्य कर रहे हैं, उनसे इस संबंध में शपथ-पत्र लिये जाने एवं उनमें कार्यरत् विशेषज्ञों जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक काउंसलर की योग्यता/अनुभव में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- इसके अलावा एआरटी क्लिनिक/एआरटी बैंक/सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया और इनके पंजीकरण से पूर्व भौतिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा एप्रोप्रियेट अथॉरिटी को अधिकृत किया गया। एप्रोप्रियेट अथॉरिटी के निर्णयों के विरुद्ध सभी प्रकरणों में अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।
- मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि आशयित दंपति/आशयित महिला/सेरोगेट माता को पात्रता प्रमाण-पत्र जिस अवधि का जारी किया जाना है, उस अवधि के बारे में अन्य राज्य की एप्रोप्रियेट अथॉरिटी द्वारा जिस अवधि का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार अवधि का निर्णय किये जाने के लिये एप्रोप्रियेट अथॉरिटी को अधिकृत किया गया है।
- इसके अलावा ज़िला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में ज़िला मेडिकल बोर्ड का गठन करने की अनुमति भी प्रदान की गई है, जिसमें एक वरिष्ठतम स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एक वरिष्ठतम शिशु रोग विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

अलवर में नवजीवन परिवारों की महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण बैच का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की 'नवजीवन योजना' के अंतर्गत अलवर ज़िले में महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य में परिवारों को अवैध शराब के दलदल से मुक्त कर कौशल प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु नवजीवन योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अवैध शराब के दलदल से मुक्त हुए परिवार के सदस्य विशेषतौर पर महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोज़गार हेतु ऋण व नियोजन का अवसर प्रदान करने की यह सकारात्मक पहल है।
- उन्होंने महिलाओं को परिवार की अर्थव्यवस्था की मज़बूत कड़ी बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से वे अपने परिवार को और अधिक आर्थिक संबल प्रदान कर सकेंगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि नवजीवन योजनांतर्गत प्रथम चरण के कौशल प्रशिक्षण बैच में अलवर शहर व अलवर ग्रामीण के नवजीवन परिवारों की 75 महिला प्रतिभागियों को 60 दिवसीय सिलाई का प्रशिक्षण स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत प्रत्येक प्रतिभागी को नि:शुल्क टूल किट उपलब्ध कराई गई है तथा प्रशिक्षण के दौरान स्वरोज़गार हेतु अनुजा निगम व बैंकों के माध्यम से न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण वितरण भी कराया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में शामिल परिवारों को पेंशन, पालनहार, कन्यादान, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना व इंदिरा महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना से भी जोड़ा जाएगा।

नोट :

जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 45 योजनाओं के लिये 628 करोड़ रुपए की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

4 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'जल जीवन मिशन' के तहत प्रदेशभर में 45 योजनाओं के लिये 628 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यों को गति मिलेगी तथा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो सकेंगे, जिससे गाँव-ढाणी तक लोगों को नल से जल उपलब्ध हो सकेगा।
- इस स्वीकृति के अंतर्गत प्रदेश के करौली ज़िले में 12 योजनाएँ, बीकानेर एवं उदयपुर में 6-6, जैसलमेर तथा पाली में 4-4, हनुमानगढ़ में 3 और अलवर, राजसमंद, सवाई माधोपुर ज़िले में 2-2 तथा श्रीगंगानगर, डूँगरपुर, सीकर, बांसवाड़ा में 1-1 योजना क्रियान्वित की जा सकेंगी। कार्यों के पूर्ण होने पर इन क्षेत्रों में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिये दिसंबर, 2019 में दिशा-निर्देश जारी हुए थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मार्च, 2024 तक शुद्ध पेयजल के लिये कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी प्राप्ति पर हर व्यक्ति को निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध होगा।
- विदित है कि राजस्थान में वर्तमान में लगभग 27 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँच रहा है तथा प्रदेश सरकार प्रत्येक परिवार को नल से जल पहुँचाने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

सात ज़िलों की छात्राओं ने महात्मा गांधी विद्यालय में सैटेलाइट और ड्रोन किया लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

4 नवंबर, 2022 को राजस्थान के जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (पूर्व राज. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय) मालवीय नगर में 3 दिवसीय 'पीको सैटेलाइट इवेंट' के ग्रैंड फिनाले में प्रदेश के सात ज़िलों से चयनित एवं प्रशिक्षित 30 छात्राओं ने छोटे सैटेलाइट और ड्रोन को संचालित किया।

प्रमुख बिंदु

- अजमेर, अलवर, बूंदी, जयपुर, भरतपुर, डूँगरपुर, झुंझुनुं ज़िलों की इन छात्राओं ने विभिन्न चरणों से गुज़र कर गत तीनदिवसीय कार्यशाला में ड्रोन एवं उपग्रह की डिज़ाइन करना, निर्माण करना और लॉन्च करना सीखा।
- विद्यालय की प्रधानाचार्या निशि सिंह ने बताया कि स्टेम, अर्थात् साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्मेटिक्स फॉर गर्ल्स इंडिया के तहत आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) राजस्थान के 10 ज़िलों में 306 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को उपग्रह, ड्रोन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिये एक साथ आए हैं, ताकि उन्हें उन्नत स्टेम कौशल के साथ सशक्त बनाकर स्टेम में शिक्षा और करियर बनाने में मदद की जाए।
- उल्लेखनीय है कि दोनों संस्थाओं ने मिलकर 2 से 4 नवंबर तक जयपुर में 'पीको सैटेलाइट इवेंट'का आयोजन किया, जिसके लिये राजस्थान के विभिन्न सरकारी स्कूलों की 30 छात्राओं ने एक कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें उन्हें ड्रोन और उपग्रह की डिज़ाइन, निर्माण और लॉन्च करना सिखाया गया।
- 500 छात्राओं के एक बैच में से चुनी गई इन 30 छात्राओं को कई कार्यशालाओं और ऑनलाइन परीक्षाओं के बाद कठोर, गहन प्रशिक्षण से गुज़रना पड़ा।
- छात्राओं द्वारा बनाए गए इन उपग्रहों द्वारा लिये गए डाटा का उपयोग भारतीय अनुसंधान परिषद और कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा।

नोट :

- छात्राओं को उपग्रह, ड्रोन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने हेतु इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आकांक्षा को बढ़ावा देने एवं उपग्रहों और ड्रोन को असेंबल करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के साथ जागरूकता, आत्मविश्वास, कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से इस परियोजना को तैयार किया गया है।

डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का जयपुर के जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में आयोजन

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2022 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में कला शिविर में 'म्हारो राजस्थान' का आयोजन तथा प्रदर्शनी में स्टॉल का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- श्रेया गुहा ने बताया कि राजस्थान विश्व में पहला प्रांत है, जहाँ क्षेत्रीय काउंसिल का गठन कर पंजीयन किया गया। कोविड के दौरान इसके ऑनलाइन इंवेट किये और अब ऑफलाइन इंवेट के माध्यम से ड्रामा, डांस, थिएटर, आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं तथा युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्षेत्रीय काउंसिल के माध्यम से कलाकारों के लिये खेल का आयोजन किया जाएगा एवं उन्हें वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक काउंसिल के महासचिव रमेश प्रसन्ना ने बताया कि कल्चर वेल्यू को क्षेत्रीय स्तर पर शुरू करने के उद्देश्य से डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की शुरुआत की गई है। गॉड अपोलो की थीम व हारमनी की तर्ज़ पर डेल्फिक काउंसिल की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है तथा इसका उद्देश्य आपसी भाईचारा, संस्कृति व परंपराओं को कायम रखना एवं विश्व में प्रसार करना है।
- जर्मन आर्ट स्कूल की इन्स लेक्सचुस ने कहा कि कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन कर राजस्थान ने एक प्रेरणा दी है तथा ऐसे प्लेटफॉर्म पर जर्मन कलाकारों को अपनी कला का आदान-प्रदान करने एवं सीखने का एक बेहतर अवसर मिलेगा।
- कार्यक्रम में जर्मन आर्ट स्कूल के विद्यार्थी राजस्थानी कलाकारों से रूबरू हुए तथा राजस्थानी कला एवं संस्कृति को समझा। उन्होंने पेंटिंग्स की विविध कलाओं के कलाकारों से जर्मन कला को साझा किया।

प्रदेश के 60 हज़ार से अधिक सरकारी स्कूलों में शुरू होगा 'चेस इन स्कूल' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2022 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बीकानेर में 66वीं ज़िलास्तरीय विद्यालयी खेलकूद के तहत शतरंज प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान बताया कि प्रदेश में 60 हज़ार से अधिक सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती (19 नवंबर) से 'चेस इन स्कूल'कार्यक्रम प्रारंभ होगा तथा इसके बाद हर महीने के तीसरे शनिवार को 'नो बैग डे'के दौरान स्कूलों में शतरंज खेला जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि देशभर में पहली बार राजस्थान में यह पहल होने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 60 हज़ार से अधिक स्कूलों में खेल ग्रांट से चेस बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्री खरीदी जाएगी और बच्चों को शतरंज में पारंगत किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि पहली बार शतरंज को स्कूली खेलों में शामिल किया गया है। इसके बाद शतरंज की ज़िला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, जिनमें भागीदारी निभाने वाले बच्चे आने वाले समय में शतरंज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में राजस्थान का नाम रोशन करेंगे।
- स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि शतरंज खेल को प्रोत्साहित करने में 'चेस इन स्कूल'देश का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा। उन्होंने दस और चौदह वर्ष आयु वर्ग में भी यह प्रतियोगिताएँ आयोजित करने की बात कही।
- प्रतियोगिता समन्वयक सेणुका हर्ष ने बताया कि ज़िलास्तरीय प्रतियोगिता के दौरान 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे चार वर्गों में भागीदारी निभाएंगे। शतरंज की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता भी 14 से 18 नवंबर से बीकानेर के रमेश इंग्लिश स्कूल में होगी। इसमें प्रदेश के 33 ज़िलों की टीमें भागीदारी निभाएंगी।

नोट :

'जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल'

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2022 को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) के प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि राज्य में आयोजित होने वाले 'इंडिया स्टोनमार्ट 2022' में 11 और 12 नवंबर को 'जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल'(जेएएफ) का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि जेएएफ विशेषरूप से 'आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस और एजुकेशन एवं इंडिया के स्टोन ट्रेडिशन'पर केंद्रित रहेगा।
- 'जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल'का उदेश्य आर्किटेक्चर के रचनात्मक क्षेत्र में नए विचारों के आदान-प्रदान, संवाद और नेटवर्किंग के लिये एक उपयुक्त मंच प्रदान करना है तथा जेएएफ में भविष्य के शहरों, पर्यावरण, आर्किटेक्चर के साथ-साथ समृद्ध स्टोन ट्रेडिशंस के अभ्यास और शिक्षा के बारे में कई तरह के विचारों पर ज़ोर दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि 'आर्किटेक्चर फेस्टिवल'का आयोजन सीडीओएस, रीको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (IIA) और राजस्थान चैप्टर नॉलेज पार्टनर हैं।
- इस फेस्टिवल में देशभर से और विदेशों के प्रख्यात आर्किटेक्ट्स भाग लेंगे तथा प्रतिभागियों में शिक्षण संकाय और महत्त्वपूर्ण आर्किटेक्चरल कॉलेजों एवं संस्थानों के छात्र भी शामिल होंगे।
- यह फेस्टिवल विभिन्न पत्थरों की उपलब्धता और गुणों के बारे में ज्ञान एवं जागरूकता को अद्यतन करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- विदित है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सीडीओएस) ने पत्थर उद्योग में प्रतिभागियों को परेशानीमुक्त चयन और सोर्सिंग के साथ-साथ सीधे संपर्क स्थापित करने के लिये कई पहल की हैं।
- यह आयोजन नए विचारों और प्रतिभाओं के उद्भव के लिसे डिज़ाइन फ्रेटरनिटी के 300 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख आर्किटेक्ट्स के साथ सीखने और संवाद के अवसर प्रदान करेगा।
- इस फेस्टिवल में राजस्थान राज्य की समृद्ध संस्कृति, विरासत और स्टोन आर्किटेक्चर के स्रोत्र के रूप में डिस्प्ले एरिना में आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनरों के 15 प्रेरक प्रोजेक्ट्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि इंडिया स्टोनमार्ट 22 का 11वाँ संस्करण 10 से 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोंस (सीडीओएस) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) सह-आयोजक हैं।

जोधपुर डिजिफेस्ट-जॉब फेयर 2022

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2022 को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा युवाओं को रोज़गार के बृहद् अवसर प्रदान करने के लिये जोधपुर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में 11 एवं 12 नवंबर को 'डिजिफेस्ट-जॉबफेयर-2022' का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि विभाग की ओर से तकनीकी नवाचारों के प्रदर्शन के लिये जयपुर के बाद जोधपुर में डिजिफेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। डिजिफेस्ट-जॉब फेयर 2022 में 20 हज़ार से अधिक युवाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- डिजिफेस्ट के दौरान ही यहाँ रोज़गार मेले का भी आयोजन होगा, जिसमें 10वीं, 12वीं तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार दिलवाया जाएगा।

नोट :

- ई एंड वाई, केपीएमजी, इंफोसिस, जी4एस, महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, रिलायंस जियो, वोडोफोन, अक्ष, एलएंडटी, स्पार्क मिंडा, बजाज मोटर्स, इंफोसिस बीपीओ, एस्सेलप्रॉपैक, डीबीकॉर्प, ताजहरि, औरियनप्रो, आइडिया इन्फिनिटी, भवन साइबरटेक, जीनस, अदानी ग्रीन, सुजलॉन, एयू फाइनेंस, आईआईएफएल, जेनपैक्ट, क्लब महिंद्रा, क्वेस कॉर्प जैसी 200 से अधिक कंपनियाँ इस जॉब फेयर में युवाओं को रोज़गार देंगी।
- आई.टी. जॉब फेयर में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी http://itjobfair-rajasthan-gov की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं तथा आई.टी. जॉब फेयर स्थल पर भी पंजीकरण करवाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। युवा क्यूआर सुविधा का उपयोग कर अपना पंजीकरण स्वयं भी कर सकेंगे। जॉब फेयर में पंजीकरण करवाया जाना नि:शुल्क है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन राजस्थान स्टार्ट-अप नीति-2022 का अनुमोदन के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को आगे बढ़ाने के लिये अहम निर्णय लिया।
  - अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, ईआरसीपी निगम को जल संसाधन विभाग/सीएडी/आईजीएनडी/एसडब्ल्यूआरपीडी के स्वामित्व की अनुपयोगी भूमि एवं भूमि से संबंधित संपत्तियों का नि:शुल्क हस्तांतरण किया जाना है। साथ ही निगम के वित्तीय प्रबंधन के लिये विभागों द्वारा हस्तांतरित भूमि का प्रबंधन/बेचान/लीज/अन्य उपयोग में लेकर प्राप्त शत-प्रतिशत आय का उपयोग निगम के कार्यों के लिये किया जाना है।
  - उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी प्रदेश के 13 ज़िलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक) के लिये पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की भी अतिमहत्वपूर्ण परियोजना है।
- मंत्रिमंडल ने नवीन राजस्थान स्टार्ट-अप नीति, 2022 का अनुमोदन किया।
  - इस नीति से प्रदेश के स्टार्ट-अप, उद्यमशील विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्ट-अप्स एवं सांस्थानिक इन्क्यूबेशन सेंटर्स को फायदा मिलेगा। प्रदेश में निवेश व रोज़गार सृजन के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 2020-21 में आई-स्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये नीति लागू करने संबंधित घोषणा की गई थी।
- मंत्रिमंडल ने बैटल कैजुअल्टी, फिजिकल कैजुअल्टी के आश्रितों को अथवा स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों तथा पैरा मिलिट्री (बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड) कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन को मंज़ूरी दी।
  - उक्त संशोधन के बाद शहीद परिवार तथा उक्त सेवाओं के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को पे-लेवल 10 तक के पदों पर नियुक्तियाँ प्रदान की जाएगी तथा पूर्व की अपेक्षा ऐसे परिवारों को बेहतर रूप से संबल प्रदान किया जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए कार्मिकों के हितों में बड़ा निर्णय लिया है। इसमें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत कार्मिक को दी गई लघु शास्तियों के मामलों में एसीपी में पारिणामिक प्रभाव को समाप्त किया जा रहा है।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 में संशोधन किया है। इससे पर्यवेक्षक के पद पर अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भी आरक्षित वर्ग के समान ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
  - महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता से पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी देय है। अब यह शिथिलता अन्य आरक्षित वर्गों के साथ-साथ अति पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी मिल सकेगी।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के समान आयु सीमा में शिथिलन देने की घोषणा की गई थी।

- मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
  - इस क्रम में राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 में भारत सरकार की 19 मई, 2018 को जारी हुई अधिसूचना के अनुसार संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।
  - उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत प्रदेश के बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली व सिरोही ज़िलों में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया था, जिस कारण बढ़े हुए क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उक्त अनुमोदन से अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 'राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज (इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट ब्रांच)' और 'राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी (स्टेट एंड सबऑर्डिनेट)' सेवाओं में भी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी 'आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन'की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।
- मंत्रिमंडल ने मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर में वृहद् उद्योग (सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साईडिंग) की स्थापना के लिये कुल 5237 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
  - इसमें ग्राम पारेवर (तहसील जैसलमेर), ग्राम सोनू (तहसील सम) तथा ग्राम लीला पारेवर (तहसील जैसलमेर) में क्रमश: 0650 हैक्टेयर प्लांट हेतु एवं 23.4587 हैक्टेयर भूमि रेलवे साईडिंग व सड़क हेतु आवंटन पर निर्णय लिया गया है।
  - यह परियोजना दो चरणों में स्थापित होगी। इनमें कुल 4200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अतिरिक्त निर्माण प्रक्रिया में भी श्रमिकों को काम मिलेगा।
- मंत्रिमंडल ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित महिला (बालिका) छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2 का पद केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही भरे जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से इन छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रही बालिकाओं की सुरक्षा एवं निजता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- मंत्रिमंडल ने बूंदी के हिंडोली में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 30 जुलाई, 2022 को अपनी बूंदी यात्रा के दौरान हिंडोली में बनने वाले आई.टी.आई. कॉलेज का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर आई.टी.आई. कॉलेज करने की घोषणा की थी।

जयपुर में आयोजित होगा दो-दिवसीय विश्व सूफी संगीत समारोह 'जहाँ-ए-खुसरो'

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिये दोदिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह 'जहाँ-ए-खुसरो'का आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल में 19 और 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सचिव गायत्री राठौड़ ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस समारोह में सूफी संगीत की मधुर ध्वनियाँ गूंजेगी। साथ ही राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। 'जहाँ-ए-खुसरो'एकता के रंग का प्रतीक है।
- उन्होंने बताया कि जयपुर को एक कल्चरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस तरह के आयोजनों और प्रस्तुतियों से राजस्थान की कला और कलाकारों को बढ़ावा मिलता है। इस समारोह में राजस्थान की दंतकथा 'मूमल'को एक स्टेज शो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और चित्रकार मुजफ्फर अली और डिजाइनर मीरा अली द्वारा डिजाइन किये गए 'जहाँ-ए-खुसरो'समारोह में जावेद अली, नूरां सिस्टर्स, जसलीन कौर, नियाजी जैसे प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे।

नेशनल टैक्सेशन अवार्ड-2022 में राजस्थान को प्राप्त हुए दो गोल्ड पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2022 को टैक्स इंडिया ऑनलाईन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड-2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य (Most Reformist State) एवं एसजीएसटी/वैट कैटेगरी (SGST/VAT Category) श्रेणियों में 'गोल्ड अवार्ड' प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- दिल्ली में आयोजित समारोह में हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी द्वारा दिये गए इस अवार्ड को राजस्थान सरकार की ओर से वित्त विभाग की संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) द्वारा ग्रहण किया गया।
- ओडिशा राज्य को इस श्रेणी में रजत तथा हरियाणा, तमिलनाडु तथा बिहार को जूरी अवार्ड प्रदान किया गया।
- राजस्थान सरकार को स्टेट वैट श्रेणी में भी प्रथम स्थान आने पर गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। ओडिशा राज्य को इस श्रेणी में रजत तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ को जूरी अवार्ड प्रदान किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा आई.एफ.एम.एस. प्लेटफॉर्म पर नवाचार करते हुए इसमें व्यावहारिक परिवर्तन किये गए हैं, प्रक्रियाओं का मानकीकरण एवं मानवीय हस्तक्षेप में कमी करने से इसे और अधिक जन उपयोगी बनाया गया, जिससे भुगतान एवं राजस्व एकत्र करने में मदद मिली है।
- इसी प्रकार राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी कानून के करों की प्रभावी वसूली की गई, जिससे गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक राजस्व एकत्रित हुआ है।
- राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित बकाया राशि के निष्पादन के लिये एमनेस्टी योजना-2021 एवं 2022 की घोषणा कर लगभग 00 लाख रूपए से अधिक प्रविष्टियाँ समाप्त कर व्यवहारियों को राहत दी गई है। इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के बजट में व्यवहारी सुविधा केंद्र की स्थापना तथा जीएसटी कानून के तहत ई-वे बिल की सीमा एक लाख रुपए तक बढ़ाकर व्यवहारियों को राहत प्रदान की गई है।
- विदित है कि टैक्स इंडिया ऑनलाईन नॉलेज फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड कर प्रबंधन में सुधार करने वाले तथा करदाताओं के योगदान को स्वीकार करने वाले राज्यों और कर कानूनों की पालना करने वाले करदाताओं, प्रौद्योगिक सेवा प्रदाताओं, करदाता हितैषी आयुक्तों एवं कर प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नीति-निर्माताओं इत्यादि सहित नौ श्रेणियों में दिया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत जज, भारत सरकार के सेवानिवृत उच्च पदाधिकारी तथा केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के सेवानिवृत सदस्य पुरस्कारों की जूरी में सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- टैक्स इंडिया ऑनलाईन की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। ऑनलाईन मीडिया के रूप में यह प्रमुख स्टार्ट-अप कंपनी के रूप में स्थापित है। टैक्स इंडिया ऑनलाईन द्वारा वर्ष 2020 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी।

कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा देने हेतु गाइडलाइन्स-2022

चर्चा में क्यों ?

11 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत्/निवासरत् विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गाइडलाइन्स-2022 को स्वीकृति दी। इस स्वीकृति से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एक तनावमुक्त तथा सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गाइडलाइन्स-2022 में विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण उत्पन्न हुए मानसिक तनाव एवं अवसाद के निराकरण हेतु मनोचिकित्सकीय सेवा प्रदान करना, प्रवेशित तथा छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की व्यवस्थाएँ, ज़िला प्रशासन स्तर पर पर्याप्त निगरानी तंत्र की स्थापना, कोचिंग छात्र-छात्राओं के लिये सुविधा केंद्र, साफ-सफाई का बेहतर प्रबंधन, कोचिंग संस्थानों के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही, कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिये आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों की दिनचर्या में साइबर कैफे की सुविधा आदि दिशा-निर्देश शामिल किये गए हैं।
- इस गाइडलाइन्स में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आईआईटी एवं मेडिकल संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने की स्थिति में उपलब्ध करियर विकल्पों के बारे में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थान छोड़ने की स्थिति में ईज़ी एक्जिट पॉलिसी एवं फीस रिफंड का प्रावधान किया गया है।
- गाइडलाइन्स के तहत एक कम्पलेन्ट पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नई गाइडलाइन्स में कोचिंग सेंटर के सभी कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आवासीय कोचिंग संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डाटा संधारित करने का प्रावधान भी गाइडलाइन्स में शामिल है। कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार की मिथ्या प्रचार की रोकथाम की व्यवस्था गाइडलाइन्स में की गई है। इन दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- कोचिंग संस्थानों द्वारा गाइडलाइन्स का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, गृह विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गाइडलाइन्स के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में ज़िलास्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ अभिभावकों, कोचिंग संस्थानों, एनजीओ के प्रतिनिधि एवं मनोवैज्ञानिक तथा मोटिवेशनल स्पीकर और ज़िले के अतिरिक्त ज़िला कलक्टर शामिल हैं।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोचिंग संस्थानों के प्रभावी नियमन के लिये बनाए गए 'राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2022' के लागू होने तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में उक्त गाइडलाइन्स को मंज़ूरी दी है।

राजस्थान डिजिफेस्ट एंड जॉब फेयर का समापन

चर्चा में क्यों ?

13 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में राजस्थान डिजिफेस्ट एंड जॉब फेयर का समापन किया।

प्रमुख बिंदु

- समापन समारोह के अवसर पर अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करते हुए बताया कि यह इंस्टीट्यूट 672.45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें विद्यार्थियों और स्टार्टअप्स सहित युवाओं को विश्वस्तरीय मंच मिलेगा।
- इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का विमोचन किया, जिससे प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा। इसमें एससी-एसटी सहित हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।
- मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों में उद्यमिता, कौशल विकास के लिये जोधपुर और पाली (वर्चुअल) में आई-स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल एंड रूरल इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं को 41.15 लाख रुपए के प्रतीकात्मक चेक पुरस्कार के रूप में वितरित किये।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर तथा चूरू में इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित हो चुके हैं।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने समारोह में प्रदेश के 12 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी वितरित की। उल्लेखनीय है कि आई-स्टार्ट के तहत अभी 3000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें इन्हें 30 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई, जिससे प्रदेश में 200 करोड़ रुपए तक का निवेश आया और 21 हज़ार से अधिक लोगों को रोज़गार मिला है।
- उन्होंने बताया कि जोधपुर में तीन दिवसीय जॉब फेयर में 23 हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा रोज़गार के लिये 3500 से अधिक युवाओं का चयन किया गया है। यहाँ 9200 से अधिक युवाओं को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इस फेयर में युवाओं को लाखों रुपए के पैकेज भी दिये गए हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने डिजिफेस्ट-2022 के बारे में बताया कि जोधपुर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की अपार संभावनाएँ हैं और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सरकार की दूरगामी सोच और नवाचारों से राजस्थान के युवाओं ने देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

12 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधिपति बिरेंद्र सिंह ने जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में वर्ष-2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर बिरेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालतें, आपसी सामंजस्य व सहयोग से आमजन के विवादों का निपटारा करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हैं तथा लोक अदालत की बेंचों में पूर्व व सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई की जाती है। पूर्व न्यायाधिपति के अनुभवों के लाभ से इन परिवादों का निपटारा आसान व सुलभ हो जाता है तथा लोक अदालत से आम जन को पूरी तरह से राहत मिलती है।
- उन्होंने बताया कि जटिल मामलों के चलते न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक हो गई है लेकिन लोक अदालत में आपसी समझौतों से मामले सुलझा लिये जाते हैं, जिससे न्यायालय का भार कम होगा। यह न्याय का सस्ता व सुलभ माध्यम है, जहाँ न किसी की हार होती है न किसी की जीत, बल्कि आपसी सामंजस्य से सफलता प्राप्त होती है।
- उन्होंने बताया कि इस बार 480 बैंचों की स्थापना की गई है, जिनमें लगभग 6 लाख मुकदमों की सुनवाई की जाएगी तथा गत लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण में पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से यह प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित कर राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त करे।
- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की गत 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों में अब तक कुल 24 लाख 86 हजार 693 प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामे से किया गया है।
- चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिये राज्य भर से 5 लाख 45 हजार 721 मामलों को चिह्नित किया गया है और राज्यभर में कुल 480 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया है।
- उच्च न्यायालय स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर द्वारा कुल 2017 मामले चिह्नित किये गए हैं और कुल 4 बैंचें गठित की गई हैं। इन बैंचों की अध्यक्षता भूतपूर्व न्यायाधिपति एसके गर्ग, न्यायाधिपति प्रशांत कुमार अग्रवाल, न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा और न्यायाधिपति गोवर्धन बाढ़दार द्वारा की जा रही है।
- ज्ञातव्य है कि लिटिगेंट्स की लोक अदालत तक पहुँच सुलभ कराने के लिये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एम एम श्रीवास्तव की प्रेरणा से लोक अदालत में रालसा- 22 ऑनलाइन लोक अदालत डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनुप्रयोग कर लोक अदालत को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया गया था। इसमें सुधार करते हुए इस प्लेटफार्म को और सरल बनाया गया है।
- इसके अलावा इस बार लोक अदालत में प्रकरण रखवाने के लिये 'न्याय रो साथी मोबाइल ऐप' को भी जनसाधारण के लिये सुलभ कराया गया है और डोर स्टेप काउंसलिंग और ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग के माध्यम से लोक अदालत को लिटिगेंट्स के घर और द्वार तक पहुँचाया जा रहा है।

नोट :

हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) एवं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मध्य एमओयू

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) एवं भारत सरकार के अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने हेतु एमओयू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक व अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण सुधांश पंत व अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक आशुतोष जोशी ने एचसीएम रीपा परिसर में इस पाँच वर्षीय MoU पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों प्रशिक्षण संस्थान इस पाँच वर्ष की अवधि में विभिन्न अनुसंधान योजना (Research Projects), संकाय सहयोग, लोक प्रशासन व सुशासन से जुड़े हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा आपसी सहमति से अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में आपसी सहयोग करेंगे।

41वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में राजस्थान मंडप का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए चौदह दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष की थीम 'वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल' के अनुरूप राजस्थान मंडप नए रूप-रंग के साथ प्रारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान मंडप का उद्घाटन राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने किया। मेला के पहले दिन ही राजस्थान मंडप राजस्थानी कला और संस्कृति के प्रतीक रूप में दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा।
- इस अवसर पर राजीव अरोड़ा ने कहा कि व्यवसाय जगत् और जनता के बीच राजस्थान राज्य सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) द्वारा प्रगति मैदान में स्थापित राजस्थान पवेलियन देश-विदेश से आए व्यापारियों और दर्शकों के लिये राजस्थान को समझने और वहाँ निवेश करने के नए अवसरों को समझने का मौका प्रदान करेगा।
- राजसीको की प्रबंध निदेशक डॉ. मनीषा अरोड़ा ने कहा कि इस बार ट्रेड फेयर में आरएसआईसी के साथ-साथ रीको, बीआईपी और उद्योग विभाग भाग ले रहे हैं। B2B और B2C घटकों के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सबसे बड़े एकीकृत व्यापार मेलों में से एक है, जिसमें भारत के लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं।
- राजस्थान मंडप के निदेशक दिनेश सेठी ने बताया कि मंडप में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार मेले में भाग लेने आए उद्यमियों द्वारा लगभग 27 स्टॉलों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें राजस्थान के विश्वप्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पादों को विशेषरूप से देश-विदेश में धूम मचाने वाली राजस्थानी हस्तशिल्प वस्तुओं में लाख की चूड़ियाँ, महिलाओं के श्रृंगार के विविध आईटम्स, टेक्सटाईल्स का सामान, चद्दरें और मोजड़ियों के उत्पादों के स्टॉल शामिल हैं।
- मंडप के मुख्य द्वार पर राजस्थान पर्यटन द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। मंडप स्थल पर रीको, रूडा और राजस्थली द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिये चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण प्रदर्शित किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप के उद्घाटन के दिन विशेष अतिथियों में स्लोवाकिया के राजदूत महामहिम राबर्ट मैक्सियन, अफगानिस्तान के उप राजदूत कादिर शाह, केन्या के राजनयिक पैट्रिक ओमिनियो सहित व्यापार और फिल्म जगत् की कई हस्तियों ने भ्रमण किया।

नोट :

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

टीकाराम जूली ने बताया कि विभाग द्वारा ज़िला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र, जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर (पेईंग गेस्ट के रूप में) अध्ययन करते हैं, उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत 2000 रुपए प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दिये जाएंगे।

- उन्होंने बताया कि योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत SC, ST, OBC, MBC, EWS और Minority के छात्रों को देय होगा।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने बताया कि योजना में छात्रों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- उन्होंने बताया कि छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जाँच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी (विभागीय ज़िलाधिकारी) को भिजवाया जाएगा तथा स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु ज़िलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (ज़िलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जाएगी। अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।

66वीं राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2022 को राजस्थान के खेल व युवा मामले एवं जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना ने टोंक ज़िले के उपखंड मालपुरा में ग्राम पंचायत लावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 66वीं राज्यस्तरीय अंडर-17 छात्र हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- अशोक चांदना ने खेलों के महत्त्व को उजागर करते हुए बताया कि खेलों के वातावरण से युवाओं में नशे का चलन खत्म होकर अपराधों में कमी आती है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में छह सौ से ज़्यादा खिलाड़ियों को अब तक सरकारी नौकरियाँ प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई हैं। सभी खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा लेकर देश का गौरव बढ़ाया है। प्रथम बार राजस्थान की महिला टीम ने वालीबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है।
- उन्होंने बताया कि लावा के खिलाड़ियों व ग्रामीणों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लावा में मिनी खेल स्टेडियम बनाने के लिये मेजर ध्यानचंद योजना से कार्य करवाने तथा अपनी ओर से 50 लाख रुपए की राशि मिनी स्टेडियम के लिये देने की घोषणा की गई है।

नोट :

डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर ज़िले के बगरू के दहमीकलां में डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय 387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सभी विधि महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना है। विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर बन जाने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और इस विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के विद्यार्थी वकालत और न्यायिक क्षेत्रों में जाकर समाज को बेहतर सेवाएँ देंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने में अग्रणी रहेंगे।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था स्थापित होने पर ही पीड़ित को सम्मान के साथ न्याय मिल सकेगा। इसी क्रम में प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष स्थापित किये गए तथा एफआईआर अनिवार्य की गई है। अब फरियादी सम्मान के साथ थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण बगरू के दहमीकलां में कुल 26 एकड़ के क्षेत्रफल में किया जायेगा। प्रथम चरण के कार्यों के लिये कुल 119.21 करोड़ रुपए फरवरी, 2022 में स्वीकृत किये गए थे।
- प्रथम चरण में इस परिसर में प्रशासनिक भवन, दो एकेडमिक ब्लॉक, गेस्ट हाउस, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, डाईनिंग हॉल, फैकल्टी एवं नॉन टीचिंग ब्लॉक, हेल्थ केयर एवं अन्य सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।
- उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि विधि शिक्षा के क्षेत्र में 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और 1650 से अधिक विधि महाविद्यालय हैं। देश में तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद राजस्थान में ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ जिससे प्रदेश के सभी विधि महाविद्यालय जुड़े हुए हैं।
- विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश के 84 विधि महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो चुके हैं तथा 28 हज़ार से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण हो चुका है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

अष्टम् राष्ट्रीय कोसीडीसी अवाड्र्स-2022

चर्चा में क्यों ?

17 नवंबर, 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने जोधपुर ज़िले के शिकारगढ़ में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) के तत्वावधान में काउन्सिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कोसीडीसी) की ओर से अष्टम् राष्ट्रीय कोसीडीसी अवाड्र्स-2022 समारोह का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री शकुंतला रावत ने कोसीडीसी की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों की कंपनियों, संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये नेशनल अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। आउटस्टैंडिंग एसआईडीसी अवार्ड ईडीसी लिमिटेड, गोवा को प्रदान किया गया।
- समारोह में आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु एवं राजस्थान के 50 उद्यमियों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया गया। इनमें सर्वाधिक 21 उद्यमी राजस्थान के हैं।
- राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों के विकास एवं विस्तार के साथ ही इनमें उत्तरोत्तर निवेश की अपार संभावनाएँ हैं और ऑन शॉप डीलिंग में क्रूड ऑयल उत्पादन करने के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

नोट :

- प्रदेश के बाड़मेर ज़िले के पचपदरा में स्थापित हो रहे पैट्रोलियम रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के उत्पादों पर आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना के लिये पचपदरा में ही रीको द्वारा राजस्थान पेट्रो जोन के रूप में एक पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जा रही है।
- उद्योग मंत्री ने बताया कि हाल ही में प्रदेश में नई राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 लागू की गई है और यह विभिन्न राज्यों में प्रचलित स्कीम्स में सबसे बेहतरीन है, जिसमें नवाचारों और अधिकतम व्यावहारिकता के साथ उद्यमों के लिये विभिन्न सहूलियतों एवं रियायतों का समावेश किया गया है। इसमें सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, जैसे कि सोलर एनर्जी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आदि भी लागू की गई हैं।
- प्रदेश में 10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश वाले उद्यमों के लिये वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू की गई है। इसके अंतर्गत 14 विभागों के अधिकारी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में एक ही छत के नीचे ऐसे उद्यमों को तीव्र गति से स्वीकृतियाँ प्रदान कर रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में पारदर्शी एवं बेहतरीन पॉलिसी फ्रेमवर्क, सुविधाजनक एवं निवेश वातावरण के अलावा उद्योगों के लिये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का तीव्र गति से विकास किया गया है तथा राज्य के प्रत्येक उपखंड में रीको का कम-से-कम एक औद्योगिक क्षेत्र होगा। पिछले माह रीको ने ऐसे 25 औद्योगिक क्षेत्र लान्च किये हैं। वर्तमान में राज्य में रीको के 400 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं।
- उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत राज्य में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन तथा जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने के लिये नई कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कर दिया गया है।
- भारतीय एवं विदेशी कंपनियों से निवेश पाने के मामले में राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान को मिलने वाला नया निवेश वर्ष 2020-21 में 37 हज़ार करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 535 प्रतिशत बढ़कर 2 लाख 37 हज़ार करोड़ रुपए पहुँच गया। इस दृष्टि से राजस्थान औद्योगिक विकास, निवेश आदि सभी क्षेत्रों में अनुकूलतम राज्य की पहचान कायम कर रहा है।

विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने जयपुर स्थित अपने राजकीय आवास से गुब्बारे उड़ाकर वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक (18 से 24 नवंबर) का शुभारंभ किया और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं इस कार्यक्रम के डेवलपमेंट पार्टनर पाथ के सहयोग से किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि आमजन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रति जागरूकता लाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक कैम्पेन के रूप में प्रदेश में 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ द्वारा इस वर्ष की थीम 'प्रिवेंटिव एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस टूगेदर'निर्धारित की गई है।
- इस अवसर पर परसादी लाल मीणा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिये अपने आसपास स्वच्छता रखें तथा गुणवत्तायुक्त स्वच्छ पौष्टिक भोजन का सेवन करें। 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना' के तहत सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की आईपीडी एवं ओपीडी सेवाएँ प्रदेशवासियों के लिये नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
- उन्होंने बताया कि इस सप्ताह के दौरान रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिये प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमों के साथ-साथ ज़िलास्तर पर क्विज़ और शपथ कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, ताकि लोग एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस के प्रति जागरूक हों।

नोट :

- एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस या रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रोग पैदा करने वाले रोगाणु, जैसे- बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई तथा पैरासाइट्स दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में किसी सूक्ष्मजीव (वायरस, बैक्टीरिया आदि) के संक्रमण के ईलाज के लिये प्रयुक्त होने वाली दवा के प्रति उस सूक्ष्मजीव द्वारा प्रतिरोध क्षमता हासिल कर लेना ही एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस है। इसके परिणामस्वरूप मानक उपचार अप्रभावी या कम असरदार रहते हैं तथा इससे बीमारी के फैलने तथा मृत्यु की संभावना रहती है। दवाओं के कम प्रभावी रहने से यह संक्रमण शरीर में बना रह जाता है तथा दूसरों में फैलने का खतरा बरकरार रहता है। इससे इलाज की लागत बढ़ती है तथा मृत्युदर में इजाफा होने की संभावना बनी रहती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस को वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में पहचाना है। ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस सर्विलांस सिस्टम के डाटा के अनुसार महत्त्वपूर्ण एंटीमाइक्रोबियल के प्रति प्रतिरोध क्षमता में वैश्विक स्तर पर इजाफा हो रहा है।
- एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंस फ्री राजस्थान के लिये राजस्थान सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान सोशल मीडिया पर भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने जीता गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में राजस्थान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता।

प्रमुख बिंदु

- 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में हरियाणा को 36-23 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान को कबड्डी में यह स्वर्ण पदक 18 साल बाद मिला है।
- विदित है कि चार दिवसीय यह चैंपियनशिप 17 नवंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार में शुरु हुई थी, जिसमें 29 राज्यों की टीमों के लगभग 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा सभी खिलाड़ियों को उपहार के तौर पर मेडल और कंबल प्रदान किये गए।

जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिये 993.51 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुरवासियों के लिये मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम निर्णय लेते हुए जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण हेतु 51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- जयपुर मेट्रो का यह फेज बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 85 किमी. है। इसमें 2.26 किमी. भूमिगत एवं 0.59 किमी एलिवेटेड भाग रहेगा।
- प्रस्ताव के अनुसार, जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण के बाद बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का संचालन हो सकेगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही आमजन को दिल्ली-आगरा हाइवे तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए फेज 1-सी एवं फेज 1-डी के निर्माण की घोषणा की गई थी। अक्टूबर, 2022 में जयपुर मेट्रो के फेज 1-डी के निर्माण के लिये 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो संचालित है।

नोट :

भीलवाड़ा के शाहपुरा में केसरी सिंह बारहठ पेनोरमा का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ के पेनोरमा निर्माण के लिये 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- अशोक गहलोत ने बताया कि केसरी सिंह बारहठ के पेनोरमा निर्माण के साथ-साथ मुख्य पेनोरमा भवन, चारदीवारी, पाथ-वे, सभागार, पुस्तकालय, ऑडियो-वीडियो सिस्टम, विभिन्न आर्ट वर्क, प्रवेश द्वार, स्टेच्यू एवं छतरी, शिलालेख सहित विभिन्न निर्माण कार्य भी होंगे।
- पेनोरमा से आमजन को वीर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की जानकारी मिलेगी। युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागृत होगी।
- इस पेनोरमा के लिये भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारहठ समाज, अमर शहीद कु. प्रतापसिंह बारहठ सेवा संस्थान और केसरी सिंह बारहठ स्मारक समिति आदि द्वारा मांग की गई थी। इन्हीं की भावनाओं के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति प्रदान की है।
- उल्लेखनीय है कि केसरीसिंह बारहठ ने राजस्थान में देश की स्वतंत्रता के लिये सर्वप्रथम क्रांति की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित किया था। उन्होंने स्वामी दयानंद और महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद एवं लोकमान्य तिलक से प्रेरित होकर सशस्त्र क्रांति के लिये प्रबल प्रयत्न करना शुरू किया था।

'कृषि में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रोत्साहन योजना'

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2022 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य में 'कृषि में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रोत्साहन योजना' चलाई जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत अध्ययन के लिये कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषि संकाय में 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को 5 हज़ार से लेकर 15 हज़ार रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है।
- राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएँ कृषि के क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल उनके परिवार की आय में वृद्धि होगी, बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में बुवाई से लेकर रोपण, जल निकासी, सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण,कटाई, खरपतवार हटाने और भंडारण तक के कार्यों में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभाती हैं।

बांसवाड़ा-नाथद्वारा, राजसमंद, बाड़मेर और उदयपुर बेल्ट में खनिज खोज का व्यापक एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2022 को राजस्थान के माइंस, पेट्रोलियम एवं जलदाय के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के बाँसवाड़ा-नाथद्वारा बेल्ट, राजसमंद बेल्ट, बाड़मेर और उदयपुर बेल्ट में राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (आरएसएमईटी) के वित्तीय सहयोग से खनिज खोज का व्यापक एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि आरंभिक सर्वेक्षणों के अनुसार राज्य के बाँसवाड़ा-नाथद्वारा बेल्ट में खनिज गोल्ड (सोने) के भंडार संभावित हैं, वहीं राजसमंद बेल्ट में खनिज एमरल्ड, बाड़मेर बेल्ट में खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उदयपुर में खनिज फास्फेट के भंडार चिह्नित किये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में आरएसएमईटी के सहयोग से एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में खनिजों के भंडार की उपलब्धता, गुणवत्ता आदि का आंकलन किया जा सके, ताकि उपलब्ध भंडारों के आधार पर ब्लॉक्स का निर्माण कर ई नीलामी की जा सके।
- उन्होंने बताया कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से खनिज एक्सप्लोरेशन कार्य को गति दी जाएगी और प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार खनिज ब्लॉक्स तैयार कर नीलाम किये जाएंगे, ताकि राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा के खोज और खनन कार्य को गति दी जा सके। इससे प्रदेश में खनिज क्षेत्र में अधिक निवेश, अधिक रोज़गार के अवसर और अधिक राजस्व प्राप्त होने के साथ ही वैश्विक पहचान बन सकेगी।
- निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि राज्य में खनिज ब्लॉकों के ऑक्शन कार्य में तेज़ी आई है। पिछले दिनों मेजर मिनरल के क्षेत्र में नागौर और जैसलमेर में लाईमस्टोन के दो ब्लॉकों की ई नीलामी की गई है।
- आरएसएमईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा राज्य में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा ड्रिलिंग कार्य में तेज़ी लाने के साथ ही प्राप्त सैंपल का समय पर परीक्षण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने किया 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही, पाली ज़िले में 350.50 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में आज 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इनके निर्माण के पश्चात् महाविद्यालयों से निकलने वाले नर्सिंग विद्यार्थी प्रदेश में बेहतर सेवाएँ देंगे।
- मुख्यमंत्री ने बाड़मेर, बाँसवाड़ा, कुम्हेर (भरतपुर), भीलवाड़ा, लालसोट (दौसा), धौलपुर, डूँगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, नाथद्वारा (राजसमंद), प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही एवं टोंक नर्सिंग महाविद्यालयों का वर्चुअल एवं पाली व चित्तौड़गढ़ में भूमि पूजन कर कुल 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा महत्त्व दिया है। इन दोनों शहरों को 'ट्विन सिटीज़'के रूप में विकसित करने का भी लंबे समय से प्रयास रहा है।
- पाली शहर में पेयजल समस्या का भी प्राथमिकता से समाधान किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण भी प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लाभ शीघ्र पाली ज़िले को भी मिलेगा।
- प्रदेश से गुज़रने वाले दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली से गुज़रता है। पिछले कार्यकाल में मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया। इस क्षेत्र में अब बृहद् स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन-रोहट-जोधपुर नोड का कायाकल्प होगा व प्रदेश के औद्योगीकरण में यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र के नज़दीक ही रिफाइनरी के आने से रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना'के माध्यम से आमजन को महँगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत परिवार हेल्थ इन्श्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत केवल 41 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री

नोट :

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक लगभग 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रुपए से अधिक का नि:शुल्क इलाज दिया गया है।

- चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज के साथ ही लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख रुपए की सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश आज मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। मात्र 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा रसोई योजना, शहरी बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, ब्याजमुक्त ऋण के लिये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग के लिये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रदेश के विद्यार्थियों को विदेश में नि:शुल्क पढ़ाई के लिये राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में अब तक 1 लाख 25 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। लगभग इतने ही सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती की घोषणा की जा चुकी है।
- निजी क्षेत्र में भी रोज़गार सृजित करने के लिये सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में जयपुर एवं जोधपुर में जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं को अच्छे पैकेज पर नौकरियाँ मिलीं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने के बाद बृहद् स्तर पर राज्य में रोज़गार सृजित होंगे।

राजस्थान आवासन मंडल स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

23 नवंबर, 2022 को राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवासन मंडल को नवाचारों एवं कायाकल्प के लिये हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि विगत वर्षों में 'बुधवार नीलामी उत्सव', ई-बिड सबमिशन एवं ई-ऑक्शन जैसे नवाचारों के ज़रिये 16 हज़ार से अधिक अधिशेष संपत्तियों के निस्तारण, कोचिंग हब, विधायक आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, एआईएस एवं एसएस रेजीडेंसी, जयपुर चौपाटी जैसी परियोजनाओं तथा प्रशासनिक सुधार के लिये किये गए सफल प्रयासों के चलते राजस्थान आवासन मंडल ने नई पहचान कायम की है।
- आवासन आयुक्त ने बताया कि बीते करीब साढ़े तीन वर्षों में मंडल को इंडियन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस, नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल नई दिल्ली, स्कॉच ग्रुप जैसी संस्थाओं से कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
- वर्ष 2020 में 'बुधवार नीलामी उत्सव'के तहत मात्र 12 दिन में 185 करोड़ रुपए मूल्य की 1213 संपत्तियों के विक्रय, वर्ष 2019 में मात्र 35 कार्यदिवसों में 1010 मकान बेचने तथा मानसरोवर एवं प्रताप नगर चौपाटी में नवंबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान पहले 5 माह में 6 लाख 10 हज़ार 670 लोगों के प्रवेश (फुट-फॉल) को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में मान्यता दी है।
- राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरे वर्ष यह सम्मान अर्जित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। हाउसिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बाद स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2022 इसी दिशा में एक और कड़ी है।

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए कई अहम निर्णय

चर्चा में क्यों ?

24 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम में संशोधन, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के प्रस्ताव पर अनुमोदन सहित कई अहम निर्णय लिये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 का अनुमोदन किया है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की पालना में तैयार इस योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोज़गार सृजित होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा। वहीं देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के प्रावधानों में इकाईयाँ 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होंगी। इन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट सहित कई प्रावधान किये गए हैं।
- मंत्रिमंडल की बैठक में 'राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' का अनुमोदन किया गया। इस नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों एवं बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिये शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाया जाएगा।
- बैठक में मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में संशोधन का भी बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन से अनुसूचित जाति/जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों (भूतपूर्व सैनिकों के अलावा) का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती नियमों में भर्ती उपरांत, उनका समायोजन उनसे संबंधित श्रेणी में किया जाता है। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं, का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।
- मंत्रिमंडलीय बैठक में राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार, प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति के वर्तमान प्रावधान को संशोधित कर 40 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 60 प्रतिशत पदोन्नति से किया जा सकेगा। इससे सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे।
- मंत्रिमंडल में राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 87.5 प्रतिशत किया गया है। इस निर्णय से कर सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के अंतर्गत राजस्थान अभियोजन सेवा में संयुक्त निदेशक के नवीन पद का सृजन, राजस्थान अभियोजन सेवा में अतिरिक्त निदेशक पद का पे-लेवल एल-20 से एल-21 तथा राजस्थान मोटर गैराज सेवा में मुख्य अधीक्षक के नवीन पद (पे-लेवल एल-17) का सृजन किया जाएगा। इससे राजस्थान अभियोजन सेवा तथा राजस्थान मोटर गैराज सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये ऑनलाइन पेंशन पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

24 नवंबर, 2022 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर.के.शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की डिजिटलाइजेशन मुहिम के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु ऑनलाइन पेंशन पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आर.के.शर्मा ने बताया कि निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन का विवरण देखने एवं पेंशन स्लिप डाउनलोड करने हेतु डिजिटल सुविधा की मांग की जा रही थी ताकि उन्हें इन कार्यों हेतु कार्यालय न आना पड़े।
- वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के विवरण त्वरित उपलब्ध कराने के मद्देनज़र विद्युत उत्पादन निगम के आई टी विभाग को निर्देशित किया गया है।
- आई टी विभाग ने उत्पादन निगम की वेबसाइट पर पेंशन डिटेल्स के नाम से सुविधा शुरू की है। इससे पेंशनर्स वित्त वर्ष में अपनी पेंशन का विवरण देख सकते हैं तथा पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- पेंशन विवरण देखने या डाउनलोड करने में समस्या होने पर आई टी विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है ताकि समस्या का तुरंत निराकरण किया जा सके।

डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलेगी 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि

चर्चा में क्यों ?

25 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक, 2022 में पदक जीतने वाले राज्य के तीन खिलाड़ियों को कुल 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव के अनुसार, डेफ ओलंपिक 2022 में डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा एवं गौरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए दिये जाएंगे। इसके अलावा डेफ राइफल शूटिंग में काँस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
- विदित है की राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत एवं काँस्य पदक विजेताओं को क्रमश: तीन करोड़, दो करोड़ तथा एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम-2022 में शिथिलन प्रदान करते हुए तीनों खिलाड़ियों को यह पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस स्वीकृति से खिलाड़ियों को आर्थिक संबल के साथ-साथ प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिये प्रेरणा मिलेगी।

जेम बॉर्स की स्थापना हेतु बैठक का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

25 नवंबर, 2022 को राजस्थान के जयपुर में जेम बॉर्स की स्थापना के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में जेम्स एंड ज्वैलरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राजीव अरोड़ा से आग्रह किया कि जौहरी बाजार में स्थित जेम्स एंड ज्वैलरी व्यापार को व्यापक रूप देने के लिये सीतापुरा में जेम बॉर्स स्थापना की जाए।
- इसके लिये 15 लाख स्क्वायर मीटर का स्थान रियायती दरों पर आवंटन किया जाए, जिससे जैम्स एंड ज्वैलरी के समस्त छोटे-छोटे व्यापारियों को समुचित स्थान उपलब्ध हो सके और राजस्थान के निर्यात को बढ़ावा मिल सके।
- जेम बॉर्स की स्थापना से जयपुर से निर्यात को समुचित बढ़ावा मिलेगा एवं युवाओं को रोज़गार के नये अवसर मिलेंगे।

नोट :

'डॉ. अंबेडकर उत्सव धाम योजना' के अंतर्गत राजस्थान के 568 गाँवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

25 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि 'डॉ. अंबेडकर उत्सव धाम योजना' के तहत प्रदेश के 568 गाँवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनके रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि यह योजना केवल 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' में चयनित गाँवों पर ही लागू की गई है। सामुदायिक हॉल अथवा भवन बनाने के लिये पायलट फेज में प्रदेश के 568 गाँवों का चयन किया गया है।
- उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 103 गाँव श्रीगंगानगर ज़िले में चयनित किये गए हैं। इसके बाद भरतपुर 68, अलवर 47, बाड़मेर 33, जोधपुर व दौसा 31-31 सहित प्रदेश के 32 ज़िलों के चयनित गाँवों में सामुदायिक हॉल/भवन बनेंगे।
- प्रत्येक गाँव में 25-25 लाख रुपए की लागत के सामुदायिक हॉल, भवनों का निर्माण होगा। यह योजना सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है।

हरि सिंह उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधानकर्त्ता के रूप में सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

26 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर कर्नाटक के बेंगलूरु में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के पशुपालन राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने राजस्थान के गंगानगर ज़िले के हरी सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये द्वितीय पुरस्कार से नवाजा।

प्रमुख बिंदु

- पशुपालन राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने तीन लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ शॉल ओढ़ाकर तथा गाय- बछड़े की प्रतिमा के साथ कन्नड़ पगड़ी पहनाकर हरी सिंह गोदारा को सम्मानित किया।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' योजनांतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालक, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्त्ता तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 'गोपाल रत्न पुरस्कार'से सम्मानित किया गया।
- राजस्थान के गंगानगर ज़िले की सुरतगढ़ तहसील के संघर गाँव के हरी सिंह गोदारा ने वर्ष 2019 में गंगमूल डेयरी द्वारा संचालित साहिवाल वंशावली चयन परियोजना अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधानकर्त्ता के रूप में अपनी सेवाएँ प्रारंभ की थीं।
- हरि सिंह द्वारा अब तक 3000 साहिवाल गायों में किये गए कृत्रिम गर्भाधान से 1800 से अधिक बछड़े/बछड़ियों का जन्म हुआ है। 60 प्रतिशत से भी अधिक सफलता दर होने के कारण ही भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कृत्रिम गर्भाधान कर्त्ता के रूप में हरी सिंह गोदारा को सम्मानित किया गया है। इस संवर्ग में प्रथम स्थान पर ओडिशा के गोपाल राणा तथा तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश के मच्छेपल्ली रहे।
- विदित है कि किसानों को ये अवार्ड प्रति वर्ष तीन समूहों [स्वदेशी मवेशी/भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दुग्ध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन पुरस्कार] में दिया जाता है।
- प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिये यह पुरस्कार मिलता है। प्रथम पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए की धनराशि, वहीं, द्वितीय स्थान पाने वाले को तीन लाख रुपए की धनराशि तथा तृतीय स्थान वाले को दो लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।

नोट :

आइईडी से निपटने में देश में तीसरे स्थान पर राजस्थान

चर्चा में क्यों ?

26 नवंबर, 2022 को राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आइईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ के डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह की अगुवाई में राजस्थान पुलिस की टीम ने 21 से 26 नवंबर तक आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में यह खिताब जीता।
- एनएसजी के महानिदेशक ने डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह को ट्रॉफी प्रदान कर राजस्थान पुलिस दल को सम्मानित किया।
- एनएसजी मानेसर में हर वर्ष आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से पुलिस और सुरक्षाबलों ने हिस्सा लिया, प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस के 16 जवानों ने डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन किया।
- डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की काउंटर आइईडी क्षमता को परखा जाता है।
- नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता के दौरान अलग-अलग परिस्थितियों से निपटने के कौशल को परखा जाता है, जिसमें आइईडी मिलने से उत्पन्न हुई स्थितियों से विभिन्न टीमों ने अपने-अपने तरीके से निपट कर बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिस आधार पर राजस्थान पुलिस की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने सेई एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिये 2,554 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिये 2554.23 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पाली एवं सिरोही ज़िलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, सेई और साबरमती नदी पर बन रहे जलाशयों से पानी प्रेशराईज पाइप लाइन, ग्रेविटी पाइप लाइन एवं टनल के माध्यम से जवाई बांध में छोड़ा जाएगा।
- जलाशयों का निर्माण पूर्ण होने पर पाली ज़िले के 9 कस्बे (पाली, रोहट, जैतारण, सुमेरपुर, बाली, देसूरी, सोजत, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन), 560 गाँव एवं सिरोही ज़िले के शिवगंज कस्बे के साथ ही 178 गाँवों की पेयजल व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में पाली एवं सिरोही ज़िले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण की घोषणा की थी।

शिल्प गुरू और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए राजस्थान के शिल्पकार

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य 'शिल्प गुरू राष्ट्रीय पुरस्कार'सम्मान समारोह में राजस्थान के पाँच सिद्धहस्त हस्तशिल्प कलाकारों को 'शिल्प गुरू पुरस्कार' एवं चौदह श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मान समारोह में शिल्प गुरू पुरस्कार विजेताओं को सम्मान स्वरूप सोने का सिक्का, 2 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण-पत्र तथा हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को एक लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

नोट :

- वर्ष 2002 में शुरू किये गए शिल्प गुरू पुरस्कार ऐसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धहस्त हस्तशिल्पियों को दिया जाता है जिन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में गुरू की भूमिका निभाते हुए संबंधित कला को आगे बढ़ाने के लिये बेहतरीन कार्य किया हो।
- वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के लिये नामित हस्तशिल्प पुस्कार विजेताओं में शामिल विनोद कुमार जांगिड़ को वर्ष 2017 के लिये चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिये, मोहन लाल सोनी को वर्ष 2017 के लिये मिनिएचर पेंटिंग के लिये, मोहन लाल शर्मा को वर्ष 2019 के लिये ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिये, आशाराम मेघवाल को 2019 और गोपाल प्रसाद शर्मा को वर्ष 2018 के लिये मिनिएचर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिये शिल्प गुरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- हस्तशिल्प के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के चौदह सिद्धहस्त शिल्पकार हैं-
  - **वर्ष 2017 के लिये** - सुनील सोनी (थेवा कला), शोकत अली (उत्सा कला) और कमलेश शर्मा (लकड़ी पर तारकशी)।
  - **वर्ष 2018 के लिये** - ओमप्रकाश जांगिड़ (चंदन की लकड़ी पर कारीगरी), सुनीता शर्मा (पैपर कटिंग कला) और प्रेमदेवी सोनावा (हेंड ब्लॉक पेंटिंग)।
  - **वर्ष 2019 के लिये** - गुलाब सिंह (सिल्वर मीनाकारी), मोहम्मद शरीफ (टाई एवं डाई कला), कमल किशोर सोनी (बोन कर्विंग), श्यामलता गहलोत (कोफ्तगिरी कला), द्वारका प्रसाद सुथार (लकड़ी की कारीगरी), दिनेश कुमार सोनी (वर्क पेंटिंग) तथा नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला (कुंदल जड़ाई मीनाकारी)।
- उल्लेखनीय है कि उक्त सम्मान समारोह में वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के लिये देशभर से नामित किये गए हस्तशिल्प से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के 30 हस्तशिल्पियों को 'शिल्प गुरू पुरस्कार'एवं 78 हस्तशिल्पियों को 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार'से सम्मानित किया गया।

सहकारिता मंत्री ने किया मंडार ग्राम सेवा सहकारी समिति में 500 मीट्रिक टन वेयर हाउस का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सिरोही ज़िले की ग्राम सेवा सहकारी समिति मंडार में 500 मीट्रिक टन वेयर हाउस का विधिवत रूप से लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश आज मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर नए आयाम स्थापित किये है।
- उन्होंने सहकारिता समितियों एवं किसानहितों के बारें में समितियों द्वारा उठाए जाने वाले फायदों व विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वेयर हाउस से इसके आसपास के क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आमजन के लिये कई योजनाएँ चलाई गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा रसोई, किसान भाईयों के लिये फसली ऋण, इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गांरटी योजना द्वारा शहरी क्षेत्र में आमजन को 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित किया गया है।

सेफ्टी अगेंस्ट वॉइलेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन (सेव) का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अपने विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के अलवर ज़िले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार 'सेफ्टी अगेंस्ट वॉइलेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन (सेव)' का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि 'सेव' नवाचार का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
- उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि यह अभियान अलवर में सफल होगा। उसके उपरांत इसे राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देशभर में अलवर ज़िला दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाकर उन्हें संबल प्रदान करने में अव्वल रहा है। अलवर ज़िला प्रशासन व ज़िले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय द्वारा 'नवाचार सक्षम अलवर'अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों को सुगमता से योजनाओं का लाभ दिया गया।
- संवाद में अध्ययन प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष जमा कराने में आने वाली परेशानियों के बारे में पालनहारों के द्वारा अवगत कराने पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में एक पोर्टल विकसित कराया जाएगा जिसमें एक बार पंजीयन करने के पश्चात् बार-बार अध्ययन प्रमाण-पत्र जमा करने से निजात मिल सकेगी। इस पोर्टल पर संबंधित शैक्षणिक संस्था ऑनलाइन ऑटो अपडेट कर सकेंगे। यह व्यवस्था यथाशीघ्र राज्य में लागू कराई जाएगी।
- यूनिसेफ राजस्थान की स्टेट हेड इजाबेल ने अपने संबोधन में कहा कि पालनहार योजना राज्य में बच्चों के सपने साकार करने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना से जरूरतमंद बच्चों को संरक्षण एवं मदद मिलने के साथ शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
- उन्होंने कहा कि यूनिसेफ के द्वारा राजस्थान में राज्य सरकार के साथ मिलकर बाल कल्याण हेतु कार्य किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में अलवर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किये गए अभियान 'सेव' का क्रियान्वयन ज़िला प्रशासन एवं यहाँ के नागरिकों के सहयोग से किया जाएगा।
- अलवर ज़िला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने कहा कि ज़िले में ज़िला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सुव्यवस्थित रूप से सक्षम अलवर अभियान संचालित कर दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में पूरे देश के लिये एक नजीर पेश की गई है।
- अलवर ज़िला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि ज़िले में 21 हज़ार पालनहार पेंशन व 29 हज़ार दिव्यांगजन पेंशन से जुड़े हैं।
- कार्यक्रम स्थल पर 27 दिव्यांगजनों ने बैनर के माध्यम से राज्य सरकार की 27 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया। दिव्यांगजनों की इस पहल की मंत्री जूली ने तारीफ कर कहा कि दिव्यांगजनों की इस टीम के इस कदम से आमजन को भी राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी जिससे जरूरतमंद व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे।

'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' एवं 'नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

29 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास से 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' एवं 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तथा नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के लोगो का अनावरण किया तथा राज्य के शिक्षा में बढ़ते कदम के तृतीय फेज के मोबाइल ऐप, दक्षता आधारित डिजिटल रिपोर्ट कार्ड तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ के पोस्टर का विमोचन भी किया।
- मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राज्य में मिड-डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाएगा। दूध का वितरण प्रार्थना सभा के बाद होगा। अध्यापक, अभिभावक या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सदस्य स्वयं दूध चखकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। योजना पर राज्य सरकार द्वारा 44 करोड़ रुपए वहन किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सेट के लिये कपड़ा मिलेगा। सिलाई के लिये प्रति विद्यार्थी 200 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाएंगे। कक्षा एक से 8 तक राजकीय विद्यालयों में करीब 67.58 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। योजना पर 500.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

नोट :